

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2021

विषय:-ज0वि0अधि0 एवं भू0व्य0अधि0-1950 की धारा-154(4)(3)(क) के अन्तर्गत डा0 अनुज सिंघल सचिव, स्वामी विवेकानन्द हैल्थ मिशन सोसाईटी, उत्तराखण्ड को ग्राम धर्मावाला तहसील- विकासनगर जिला देहरादून में 02 बीघा भूमि कय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-352/12ए-85 (2020-23) डी0एल0आर0सी0-2021, दिनांक 14 सितम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डॉ0 अनुज सिंघल सचिव, स्वामी विवेकानन्द हैल्थ मिशन सोसाईटी, उत्तराखण्ड, बी-207, पैसिफिक एस्टेट, अनुराग चौक, बसंत विहार, देहरादून को ग्राम धर्मावाला तहसील विकासनगर जिला देहरादून के खाता संख्या-182 में खसरा नं0-641ग रकबा 0.0330 है0, 642 रकबा 0.0600 है0, 643ख रकबा 0.0600 है0 कुल रकबा 0.1530 है0 (02 बीघा) भूमि आक्सीजन जनरेशन प्लान्ट स्थापित करने हेतु कय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ0 अनुज सिंघल सचिव, स्वामी विवेकानन्द हैल्थ मिशन सोसाईटी, उत्तराखण्ड, बी-207, पैसिफिक एस्टेट, अनुराग चौक, बसंत विहार, देहरादून को ग्राम धर्मावाला तहसील विकासनगर जिला देहरादून के खाता संख्या-182 में खसरा नं0-641ग रकबा 0.0330 है0, 642 रकबा 0.0600 है0, 643ख रकबा 0.0600 है0 कुल रकबा 0.1530 है0 (02 बीघा) भूमि आक्सीजन जनरेशन प्लान्ट स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154 (4)(3)(क)(i) के अन्तर्गत कय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (आक्सीजन जनरेशन प्लान्ट स्थापित करने हेतु) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 3- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 5- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 6- ट्रस्ट द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग आक्सीजन जनरेशन प्लान्ट स्थापित करने के लिए ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यों हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
- 7- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।
- 8- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 9- भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है।
- 10- अन्य किसी प्रकार की विधिक अनियमितता के लिए संस्था पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होगी।
- 11- सम्बन्धित सोसाईटी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थों का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी उस भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 13- ट्रस्ट को योजना प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी यथा आवश्यक स्वीकृतियां समिति द्वारा प्राप्त की जायेगी।
- 14- उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में अथवा किन्हीं अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 3- कृपया, तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
सचिव।

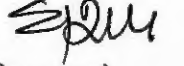
संख्या-1536/XVIII(II)/2021, तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- डॉ० अनुज सिंघल सचिव, स्वामी विवेकानन्द हैल्थ मिशन सोसाईटी, उत्तराखण्ड, बी-207, पैसिफिक एस्टेट, अनुराग चौक, बसंत विहार, देहरादून।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गीता शर्मा)

अनु सचिव।

